

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून: दिनांक 22 मई, 2014.

विषय:— जनपद—देहरादून के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, केराड़ के निमगा गेरवा तोक समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.10 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को 15 वर्षों की लीज पर दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2648/2जी-455(दे०दून) दिनांक 10-04-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद—देहरादून के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, केराड़ के निमगा गेरवा तोक समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.10 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को 15 वर्षों की लीज पर दिये जाने की अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 03-01-2005 तथा पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 13-02-2014 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है :-

1. प्रश्नगत वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
5. वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
7. वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के निर्माण व रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
9. परियोजना के निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
10. प्रस्तावित वन भूमि को अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी वन विभाग को वानिकी कार्यों के लिए निःशुल्क जलापूर्ति करेगा।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पाईप हेतु खोदी गई नाली में पाईप डालने के उपरान्त पुनः ठीक से मिट्टी भरान किया जायेगा व भूक्षरण को रोकने हेतु आवश्यक वानस्पतिक प्रजातियों/घास/झाड़ियों का रोपण किया जायेगा।
 13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दोनों इन्टेक चैम्बर से जल स्रोत से विद्यमान जल के 50 प्रतिशत से अधिक का विदोहन नहीं किया जायेगा और इन्टेक चैम्बर भी इसी के अनुसार निर्मित किये जायेंगे।
 14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नाली से उत्सर्जित मलवे को सुरक्षित स्थल पर ढुलान करके ले जाया जायेगा।
 15. प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त, 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित कार्य स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण की धनराशियों को भारत सरकार के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को RTGS के माध्यम से स्थानान्तरित कर दिया गया है।
 16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलवे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल पुनर्वास पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।
 17. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग से विधीक्षित करवाया जायेगा व उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पट्टा विलेख शासन द्वारा विधीक्षित किये जाने के उपरान्त शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी व प्रयोक्ता एजेन्सी के मध्य निष्पादित किया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्या-198/7-जी0-सी0-89-3-98, दिनांक 19-6-89 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक "0070"-अन्य प्रशासनिक सेवायें-01-न्याय प्रशासन-501-सेवायें और सेवा फीस-01 -की सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही" के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।
2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 104/26/प्र0स0-आ0व0ग्रा0वि0 दि0 1-1-2001, कार्यालय ज्ञाप सं0-110/26/प्र0स0-आ0व0ग्रा0वि0 दि0-4-1-2001 एवं उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2600/वि.अनु.-3/2003 दिनांक 4-2-2003 के अनुसार प्रस्तावित वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम को निःशुल्क हस्तान्तरित की जायेगी।

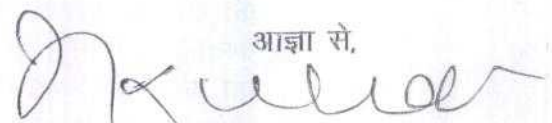
भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्या-एस0जी0: 308 /7-1-2014-700(377)/2013 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद-देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पुरोड़ी, चकराता।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, (NIC) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन.आई.सी. की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



आज्ञा से,
(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।